



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 दिसम्बर, 2004/27 अग्रहायण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2004

संख्या पी० बी० डब्ल्यू०-बी० ए०(7) 1-82/04.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा में मण्डलीय भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : चम्बा

तहसील : भरमौर

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघा बिस्वा)
भरमौर	1663/896	0 2
किता . . 1		0 2

मत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव खलियार, तहसील सदर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-20 को चौड़ा करने हेतु।

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी)ए(7)1-59/2004.

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2004.

विस्तृत विवरणी			1	2	3
जिला : मण्डी					
		क्षेत्र			
गांव	खसरा नं०	वर्ग मीटर			
1	2	3			
खलियार	47/1	9 75	1271/61		9 60
	49/1	32 70	275/1		560 65
	54/1	82 50	279/1		159 75
	56/1	135 00	280/1		217 14
	1272/61	9 09	282/2		16 17
			281		6 30
			282/1		9 80
			283/1		27 72
			284/1		7 50

1	2	3	1	2	3	4	5
	285/1	16 43		50/1	0 02 02		
	1016/307/1	7 23		133/1	0 07 02		
	1017/307/1	40 75		293/135/1	0 07 07		
	309/1	24 75		294/135/1	0 02 07		
	312/1	69 25					
	321/1	71 25	किता .. 7		1 01 12		
	743/1	33 00					
	743/2	9 04	मसवाहा	187/1	0 01 11		
	744/1	15 60		188/1	0 00 02		
	998/1	93 65		189/1	0 01 00		
	999/1	16 00		376/1	0 00 16		
	1067/1001/1	4 90		378/1	0 03 03		
	1078/1159/101/1	16 80		377/1	0 00 08		
	708/1	21 50		383/1	0 01 05		
	1003/1	7 83		384/1	0 00 12		
	1005/1	17 00		391/1	0 01 18		
	1005/2	0 75		392/1	0 02 07		
	1008/1	53 00		447/1	0 03 11		
किता .. 32		1811 30	किता .. 11		0 16 13		
तहसील : जोगिन्दरनगर			उरला	453/1	0 06 00		
				456/1	0 02 00		
*मुहाल नागण बंहली/336, मसवाहन/352, उरला तथा बडावाहन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी में उरला कोटरूपी चुम्कु सड़क के निर्माण हेतु।			किता .. 2		0 08 00		
संख्या पी0 बी0 डब्लू0(बी)ए(7)1-75/2004.			बडावाहन	117/1	0 04 05		
शिमला-2, 18 नवम्बर, 2004.				128/1	0 03 18		
				129/1	0 00 17		
				133	0 02 07		
				134	0 00 15		
				135	0 02 10		
				136/1	0 02 06		
				142/1	0 13 02		
				164/1	0 07 14		
			किता .. 9		1 17 14		

शिमला-2, 23 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 बी0 डब्लू0(बी)ए(7)1-44/04.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मलोह/102, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में सुन्दरनगर-मलोह सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह शेषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण							
जिला : मण्डी			तहसील : सुन्दरनगर				
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र			1	2	3 4 5
		बो०	बि०	वि०			
1	2	3	4	5			
मलोह/102	2/1	0	00	17	299/1		0 00 12
	9/1	0	00	06	300/1		0 02 14
	14/1	0	01	01	345/1		0 00 15
	15/1	0	01	15	368/1		0 00 06
	16/1	0	01	10	370/1		0 02 12
	16/2	0	00	14	375/3		0 02 09
	17	0	00	10	381/1		0 00 18
	18	0	05	01	379/1		0 00 07
	19	0	04	04	382/1		0 00 13
	7/1	0	01	01	385/1		0 00 19
	29/1	0	06	07	355		0 00 18
	27/1	0	01	14	356/1		0 00 15
	31/1	0	02	10	339/1		0 00 04
	32/1	0	01	05	354/1		0 01 04
	34/1	0	00	12	348/1		0 00 14
	141/1	0	00	12	301		0 00 13
	1203/142/1	0	00	16	303		0 00 04
	139/1	0	01	08	333/1		0 00 14
	138/1	0	02	09	333/2		0 04 14
	136/1	0	06	09	337/1		0 05 05
	1187/128/1	0	00	17	391/1		0 00 19
	129/1	0	01	06	392/2		0 01 10
	130	0	01	10	222/1		0 01 13
	131	0	01	12	221/1		0 00 15
	132/1	0	04	09	219		0 00 12
	133	0	04	00	215		0 01 00
	125/1	0	03	07	216		0 03 06
	124/1	0	01	17	217		0 01 16
	117	0	04	19	386		0 00 04
	118/1	0	03	05	388/1		0 03 19
	116/1	0	00	13	389/1		0 00 07
	114/1	0	00	02	390/1		0 00 15
	298/1	0	00	07	402/1		0 03 00
					214/1		0 01 05
					455		0 05 05
					456		0 03 10

2	3	4	5	1	2	3	4	5
393	0	02	08		1185/577/1	0	05	04
394	0	02	08		579/1	0	01	10
395/1	0	01	12		778/1	0	01	09
220/1	0	01	16		776/1	0	01	10
397/1	0	04	03		775/1	0	00	10
457	0	02	02		775/2	0	00	10
458	0	03	13		584/1	0	04	11
454	0	03	08		585/1	0	00	11
453	0	06	18		591/1	0	16	18
428/1	0	02	01		592/1	0	03	17
428/2	0	00	09		652/1	0	00	08
472/1	0	01	12		652/3	0	03	17
472/2	0	02	08		654/2	0	06	05
438	0	02	04		657/2	0	04	05
439	0	02	02		676/1	0	06	10
440	0	00	18		1205/658	0	07	00
441	0	01	00		659/1	0	03	14
473/1	0	03	13		659/3	0	02	17
520	0	01	18		659/2	0	06	00
514/1	0	00	04		659/4	0	05	01
516/1	0	01	11		741/1	0	03	18
519/1	0	01	13		743/1	0	00	19
530	0	03	12		613/1	0	02	15
525	0	01	14		767/1	0	03	00
526	0	01	03		770/1	0	00	16
522	0	02	16		766/1	0	09	05
523/1	0	00	08		611/1	0	02	17
511/1	0	00	14		611/2	0	13	17
531/1	0	02	08		614/1	0	02	04
536	0	03	12		615/1	0	08	00
537	0	01	12		617/1	0	06	19
532/1	0	06	11		603/1	0	00	07
533	0	01	15		335/1	0	03	04
535	0	02	00		518/1	0	07	11
534/1	0	00	13		346/1	0	00	19
544	0	00	15		648/1	0	01	15
545	0	01	14		137	0	01	11
1194/812/1	0	00	04		334	0	00	16
811/1	0	00	08		331/1	0	00	18
810/1	0	00	08		470/1	0	00	08
786/1	0	00	10		675	0	00	18
547/1	0	00	03					
787	0	01	16					
				कित्तः ..	153	16	03	27

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2004

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)77/2001. - यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कीड़, नागड़ी, गनेड़ी, बठुंह, शकोह, जलैल तथा लोहारड़ा, तहसील व जिला शिमला में (1) शोधी-सलाणा, (2) सनाणा-सरी, (3) तारादेवी गम्बर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र) शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फील्ड, शिमला-3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला		तहसील : शिमला (ग्रामीण)		1	2	3	4
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघा बिस्वा)					
1	2	3	4				
कीड़	48/1	0	2	226/1	0	1	
	98/1	0	4	222/1	0	6	
	128/17/1	0	2	214/1	0	2	
				212/1	0	12	
				300/1	0	2	
				297/1	0	2	
				298/1	0	3	
				290/1	0	8	
				304/1	0	1	
				305/1	0	1	
किता .. 3		0	8	289/1	0	4	
नागड़ी	18/1	0	1	288/1	0	7	
	173/23/1	0	10	343/1	0	4	
	172/23/1	0	4	345/1	0	5	
	32/1	0	3	349/1	0	4	
	29/1	0	2	350/1	0	6	
	28/1	0	3	251/1	0	5	
	175/27/1	0	10				
किता .. 7		1	13	किता .. 22	5	0	
जलैल	79/1	0	12	गनेड़ी	17/1	0	7
	142/1	0	7		20/1	0	3
	143/1	0	4		21/1	0	9
	224/1	0	1		26/1	0	5
	225	0	3		27/1	0	2
					69/1	0	11
					76/1	0	5

1	2	3	4	1	2	3	4
	115/1	0	11		163/1	1	0
	116/1	0	8		162/1	0	1
	134/1	0	2		226-227/183/1	0	13
	135/1	0	3		180/1	0	12
	136/1	0	1				
	138/1	0	6	किता ..	11	5	9
	147/1	0	2				
	148/1	0	4	शकोह	7/1	0	11
	149/1	0	4		8/1	0	2
	152/1	0	6		9/1	0	12
	155/1	0	7		10/1	0	5
	156/1	0	8		36/1	0	2
					34/1	0	4
					37/1	0	2
किता ..	19	5	4				
ठूह	18/1	0	14	किता ..	7	1	18
	17/1	0	4				
	13/1	0	13	सोहारड़ा	5/3/1	1	5
	12/1	0	12		6/1/1	0	16
	11/1	0	4		7/1/1	0	7
	103/1	0	9				
	116/1	0	7	किता ..	3	2	8

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।

अन्तर्गत अपील हेतु याचिका दायर की, जिसका फैसला दिनांक 2-9-2004 को हुआ जिसमें उक्त न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्वाचन अवैध घोषित किया।

उपरोक्त न्यायालय के फैसले अनुसार श्री पूर्ण चन्द उप-प्रधान, ग्राम पंचायत परछोड हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) ती के अन्तर्गत अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो चुके हैं।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, चम्पा, जिला चम्पा (हि0 प्र0) उप-प्रधान ग्राम पंचायत परछोड के पद को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत रिक्त घोषित करता हूँ, यदि उनके पास पंचायत की चल-चल संपत्ति, धन राशि हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत परछोड को सौंप दें।

राहुल आनन्द,
भा0 प्र0 से0,
उपायुक्त, चम्पा।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 4 नवम्बर, 2004

स0 पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-ई0 015/85/540-9209.—इस कार्यालय को ग्राम पंचायत कमनाला से प्राप्त प्रस्ताव सं0-3, दिनांक 7-8-2004, के अन्तर्गत जिला अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, स्थित धर्मशाला द्वारा दिनांक 29-10-2004 को की गई जांच अनुसार अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/02 के पैरा सं0-5 (3) (1) अनुसार आपके द्वारा प्रमाणक सं0-32, दिनांक 14-06-2001 के अन्तर्गत 4000 ईंटे, प्रमाणक सं0 41, दिनांक 27-6-2001 के अन्तर्गत 8000 ईंटे तथा प्रमाणक सं0 63, दिनांक 4-11-2001 के अन्तर्गत 3000 ईंटे मु0 2000/- रु0 प्रति हजार की दर से क्रन की गई थी जबकि प्रमाणक संख्या 110, दिनांक 25-2-2002 के अन्तर्गत 7500 ईंटे मु0 1950/- रुपये प्रति हजार की दर से क्रय की गई। इस प्रकार आपके द्वारा मु0 750/- रुपये की अधिक अदायगी उक्त ईंटों की की गई, जो कि आपसे वसूली योग्य बनती है।

अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/02 के पैरा सं0-5(3)(3) अनुसार मु0 10,000/- रु0 का फर्नीचर तथा मु0 1150/- रु0 का छत वाला पंखा बिना प्रशासकीय स्वीकृति क्रय किया गया है जिसके लिए आप एवं सचिव पंचायत बराबर के दोषी पाये गये हैं तथा मु0 5575/- रुपये श्री जरम सिंह एवं मु0 5575/- रु0 श्री राजिन्दर कुमार तत्कालीन सचिव से वसूली योग्य बनते हैं।

पैरा सं0-11(2) अनुसार मु0 3947.59 रुपये की राशि प्रधान से वसूली योग्य बनती है जिसके लिए प्रधान द्वारा सचिव को अपने ब्यान में दोषी बताया गया है परन्तु प्रधान द्वारा विभागीय आदेशों की उल्लंघना करके अधिक राशि व्यय सभा निधि से की गई है। इस प्रकार प्रधान श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्दर कुमार तत्कालीन सचिव दोनों दोषी पाये गये हैं। अतः राशि आप दोनों से बराबर वसूली योग्य है।

अंकेक्षण पत्र अवधि 4/02 से 3/03 के पैरा सं0 2(3) अनुसार मु0 34023/- रु0 के मस्टर रोल कमेटी द्वारा पारित नहीं किये गए जिसके लिए प्रधान द्वारा अपने ब्यान में तत्कालीन सचिव को दोषी बताया गया है जबकि इस आपत्ति के लिए श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्दर कुमार सचिव दोनों दोषी पाये गये हैं।

पैरा सं० 2(4) अनुसार मु० 5500/- रु० का खेल सामान बिना बजट आपके द्वारा क्रय किया गया था परन्तु आपने अपने व्यय में इसके लिए भी सचिव को ही दोषी ठहराया है। सचिव का भी दायित्व था कि वह बजट प्रावधान को देख लेते। इस प्रकार श्री जरम सिंह के साथ-साथ तत्कालीन सचिव भी इसमें बराबर के दोषी हैं तथा मु० 2750/- रु० जरम सिंह तथा मु० 2750/- रु० श्री राजिन्दर कुमार से वसूली योग्य बनते हैं।

पैरा सं० 2(7) अनुसार दिनांक 12-11-2002 को मु० 4000/- रु० व दिनांक 21-6-2002 को मु० 6000/- रु० बैंक से बिना प्रस्ताव पंचायत बैठक पारित किए आप एवं तत्कालीन सचिव द्वारा निकासी की गई है इसके लिए सचिव व प्रधान बराबर के दोषी पाये गये हैं।

पैरा सं० 8(3) अनुसार आपके द्वारा पंचायत धनराशि अनाधिकृत रूप से रखने पर मु० 434/- रु० व्याज वसूली योग्य है। आपने अपने व्यय में उक्त राशि जमा पंचायत निधि कर दी गई बताई है परन्तु यह राशि पंचायत रोकड़ में दर्ज नहीं पाई गई, जिससे आपका व्यय असत्य सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त आपने मु० 534/- रु० नकद शेष अपने पास रखा है जो कि आपसे वसूली योग्य है।

क्योंकि इस प्रकार श्री जरम सिंह, प्रधानग्राम पंचायत कमनाला के विरुद्ध पंचायत निधि का दुरुपयोग करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा के आरोप प्रकट हुए हैं।

अतः हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142-क के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ। आपका उत्तर इस पत्र प्राप्त के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, नूरपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है तथा मामले में आगामी कार्यवाही हेतु यह कार्यालय विवश होगा।

संलग्नक दोषारोपण सूचि।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-1

अभिकथन जिनके अन्तर्गत श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर के विरुद्ध आरोप-पत्र अधिरोपित किया गया:—

1. क्योंकि श्री जरम सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर द्वारा अंकेक्षण-पत्र अवधि 4/01 से 3/02 के पैरा सं० 5(III)(1) के अन्तर्गत दिनांक 29-10-2004 को जिला अंकेक्षण अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला की जांच अनुसार पाया गया कि आपके द्वारा प्रमाणिक सं०-32 दिनांक 14-6-2001 के अन्तर्गत 4000 ईटें प्रमाणिक सं०-41, दिनांक 27-06-2001 के अन्तर्गत 8000 ईटें तथा प्रमाणिक सं०-63, दिनांक 5-11-2001 के अन्तर्गत 3000 ईटें मु० 2000/- रुपये प्रति हजार की दर से क्रय की गई थी जबकि प्रमाणिक सं०-110, दिनांक 25-2-2002, के अन्तर्गत 7500 ईटें मु० 1950/- रु० प्रति हजार की दर से क्रय की गई। इस प्रकार आपके द्वारा मु० 750/- रु० की अधिक अदायगी उक्त ईटों की गई जो कि आपसे वसूली योग्य बनती है।

2. अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/02 पैरा सं० 5(III) (iii) अनुसार मु० 10,000/- रु० का फर्नीचर तथा मु० 1150/- रु० का छत वाला पंखा बिना प्रशासकीय स्वीकृति क्रय किया गया है जिसके लिए आप एवं सचिव (पंचायत) बराबरी के दोषी पाये गये हैं तथा मु० 5575/- रु० श्री जरम सिंह एवं मु० 5575 रु० श्री राजिन्द्र कुमार तत्कालीन सचिव से वसूली योग्य बनते हैं।

3. पैरा सं०-11/ii/अनुसार मु० 3947.59/- रु० की राशि प्रधान में वसूली योग्य बनती है जिसके लिये प्रधान द्वारा सचिव को अपने व्यय में दोषी बताया गया है। परन्तु प्रधान द्वारा विभागीय आदेशों की उल्लंघना करके अधिक राशि व्यय सभा निधि से की गई है। इस प्रकार प्रधान श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्द्र कुमार तत्कालीन सचिव दोनों दोषी पाये गये हैं। अतः राशि आप दोनों से बराबर वसूली योग्य है।

4. अंकेक्षण पत्र अवधि 4/02 से 3/03 के पैरा सं० 2-(3) अनुसार मु० 34023/- रु० के मस्टर रोल कमेटी द्वारा पारित नहीं किये गये जिसके लिए प्रधान द्वारा अपने व्यय में तत्कालीन सचिव को दोषी बताया गया है जबकि इस आपत्ति के लिए श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्द्र कुमार सचिव दोनों दोषी पाए गये हैं।

5. पैरा सं० 2(4) के अनुसार मु० 5500/- रु० का खेल सामान बिना बजट आपके द्वारा क्रय किया गया था परन्तु आपने अपने व्यय में इसके लिए भी सचिव को ही दोषी ठहराया है। सचिव का भी दायित्व था कि वह बजट प्रावधान को देख लेते। इस प्रकार श्री जरम सिंह के साथ-साथ तत्कालीन सचिव भी इसमें बराबर के दोषी हैं तथा मु० 2750 रु० श्री जरम सिंह तथा मु० 2750/- रु० श्री राजिन्द्र कुमार से वसूली योग्य बनते हैं।

6. पैरा सं० 2(7) अनुसार दिनांक 12-11-2002 को मु० 4000/- रु० व दिनांक 21-6-2002 को मु० 6000/- रु० बैंक से बिना प्रस्ताव पंचायत बैठक पारित किये आप एवं तत्कालीन सचिव द्वारा निकासी की गई है इसके लिए सचिव व प्रधान बराबर के दोषी पाये गये हैं।

7. पैरा सं० 8(3) अनुसार आपके द्वारा पंचायत धनराशि अनाधिकृत रूप में रखने पर मु० 434/- रुपये ब्याज वसूली योग्य है। आपने अपने व्यय में उक्त राशि जमा पंचायत निधि कर दी गई बताई है परन्तु यह राशि पंचायत रोकड़ में दर्ज नहीं पाई गई जिससे आपका व्यय असत्य सिद्ध होता है इसके अतिरिक्त आपने मु० 534/- रु० नकद शेष अपने पास रखा है जो कि वसूली योग्य है।

अतः प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर का यह कृत्य हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम व नियम की अवहेलना है जिस कारण उक्त प्रधान के विरुद्ध हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) जिसे हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 142(1)(क) के अन्तर्गत पढ़ा जाये कार्यवाही की जानी वांछित है।

हस्ताक्षरित/-

जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-2

प्रतिकथन जिनके अन्तर्गत श्री जरम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर के विरुद्ध लगाये गए आरोप सत्य सिद्ध हुए हैं :—

1. यह कि श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर द्वारा अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/02 के पैरा सं० 5(iii) (1) के अन्तर्गत दिनांक 29-10-2004 को जिला अंकेक्षण अधिकारी

कांगड़ा स्थित धर्मशाला की जांच अनुसार पाया गया कि आपके द्वारा प्रमाणिक सं० 32, दिनांक 14-06-2001 के अन्तर्गत 4000 ईटें प्रमाणिक सं० 41, दिनांक 27-6-2001 के अन्तर्गत 8000 ईटें तथा प्रमाणिक सं० 63, दिनांक 5-11-2001 के अन्तर्गत 3000 ईटें मु० 2000/- रु० प्रति हजार की दर से क्रय की गई थी जबकि प्रमाणिक सं० 110, दिनांक 25-02-2002 के अन्तर्गत 7500 ईटें मु० 1950/- रु० प्रति हजार की दर से क्रय की गई। इस प्रकार आपके द्वारा मु० 750/- रु० की अधिक अदायगी उक्त ईटों की की गई जो कि आपसे वसूली योग्य बनती है।

2. अंकेक्षण पत्र अर्वाधि 4/01 से 3/02 पैरा सं० 5(iii)(iii) अनुसार मु० 10,000/- रु० का फर्नीचर तथा मु० 1150/- रु० का छत वाला पंखा बिना प्रशासकीय स्वीकृति क्रय किया गया है जिसके लिए आप एवं सचिव (पंचायत) बराबर के दोषी पाये गये हैं तथा मु० 5575/- रु० श्री जरम सिंह एवं मु० 5575/- रु० श्री राजिन्द्र कुमार तत्कालीन सचिव से वसूली योग्य होते हैं।

3. पैरा सं० 11(ii) अनुसार मु० 3947.59 रु० की राशि प्रधान से वसूली योग्य बनती है जिसके लिए प्रधान द्वारा सचिव को अपने व्यान में दोषी बताया गया है, परन्तु प्रधान द्वारा विभागीय आदेशों की उल्लंघना करके अधिक राशि व्यय सभा निधि से की गई है। इस प्रकार प्रधान श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्द्र कुमार तत्कालीन सचिव दोनों दोषी पाये गये हैं। अतः राशि आप दोनों से बराबर वसूली योग्य है।

4. अंकेक्षण पत्र अर्वाधि 4/02 से 3/03 के पैरा सं० 2 (3) अनुसार मु० 34023/- रु० के मस्टर रोल कमेटी द्वारा पारित नहीं किये गये जिसके लिए प्रधान द्वारा अपने व्यान में तत्कालीन सचिव को दोषी बताया गया है जबकि इस आपत्ति के लिए श्री जरम सिंह एवं श्री राजिन्द्र कुमार, सचिव दोनों दोषी पाये गये हैं।

5. पैरा सं० 2(4) अनुसार मु० 5500/- रु० का खेल सामान बिना बजट आपके द्वारा क्रय किया गया था परन्तु आपने अपने व्यान में इसके लिए भी सचिव को ही दोषी ठहराया है। सचिव का भी दायित्व था कि बजट प्रावधान को देख लेते। इस प्रकार जरम सिंह के साथ-साथ तत्कालीन सचिव भी इसमें बराबर के दोषी हैं तथा मु० 2750/- रु० श्री जरम सिंह तथा मु० 2750/- रु० श्री राजिन्द्र कुमार से वसूली योग्य बनते हैं।

6. पैरा सं० 2(7) अनुसार दिनांक 12-11-2002 को मु० 4000/- रु० व दिनांक 21-6-2002 को मु० 6000/- रु० बैंक से बिना प्रस्ताव पंचायत बैठक पारित किये आप एवं तत्कालीन सचिव द्वारा निकासी की गई है इसके लिए सचिव व प्रधान बराबर के दोषी पाये गये हैं।

7. पैरा सं० 8(3) अनुसार आपके द्वारा पंचायत धनराशि अनाधिकृत रूप से रखने पर मु० 434/- रु० ब्याज वसूली योग्य है। आपने अपने व्यान में उक्त राशि जमा पंचायत निधि कर दी गई बताई है परन्तु यह राशि पंचायत गोकड़ में दर्ज नहीं पाई गई जिससे आपका व्यान असत्य सिद्ध होता है इसके अतिरिक्त आपने मु० 534/- रु० नकद शेष अपने पास रखा है जो कि वसूली योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला पर लगाये गये आरोप तथ्यों के अनुकूल हैं व उक्त प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। अतः प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला के विरुद्ध हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) जिसे हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 (1)(क) के अन्तर्गत पढ़ा जाये कार्यवाही की जानी वांछित है।

हस्ताक्षरित/-

जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।